

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 24, गुरुवार, शाके 1945-मार्च 14, 2024 Phalguna 24, Thursday, Saka 1945- March 14, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ायें।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

अधिसूचना

गंगापुर सिटी, फरवरी 02, 2024

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार एवम राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प01 150 राज0/6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार भरतपुर जिले की तहसील तलावड़ा (ग्राम- बाढटटवाडा) एल.सी.नंबर 172 पर रेल्वे आवर ब्रिज निर्माण में निम्नानुसार प्रभावित गाँवोंमें भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम- बाढटटवाडाविवरण

क्र.सं.	खसरासं.	कुलरकबा (है०)	अवाप्तकिए जाने वाला क्षेत्रफल (है०)
1	2	3	4
1	111	0.61	0.0134
2	132	0.28	0.0394
3	478/132	0.28	0.0412
4	56	0.45	0.1558
5	55	0.49	0.063
6	53	0.19	0.0542
7	52	0.41	0.0116
8	110	1.6	0.5408
9	148	1.4	0.0009
10	109	0.23	0.0137
11	107	1.11	0.0234
12	56/464	0.18	0.0171
योग	किता 12		0.9745

- अधिसूचित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या ३०/२०१३) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
- सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड गंगापुर सिटी व उनके स्टाफ/कर्मचारी को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोरकरने व परियोजना के किर्यान्वन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा होने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बयाना द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जायेगा।
- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।
 1. संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
 2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
 3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/ आपतियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवम सामाजिक समाघात प्रबन्ध रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
 5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत और शून्य बना देगा।

6.सामाजिक समाधान निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण सम्पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है।

सुनील गुप्ता,
सयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.वि.राज.जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।